

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4738  
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

**आंध्र प्रदेश में न्याय विकास परियोजनाएं**

**4738. श्री जी. लक्ष्मीनारायण :**

**श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में न्याय विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) चल रही, विलंबित या पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं सहित इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है ;

(घ) क्या उक्त राज्य में न्याय विकास योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हां, तो उनके अनुमोदन या कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने तथा चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ङ) :** भारत सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की भौतिक अवसंरचना में उत्तरोत्तर सुधार करने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए वकील हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय इकाइयों का संनिर्माण भी समाविष्ट है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे चल रही और पूरी हो चुकी परियोजना को वास्तविक समय में जियो-टैग करें और इसे न्याय विकास पोर्टल पर प्रदर्शित करें, जो न्यायिक अवसंरचना परियोजना की प्रगति और समयबद्ध समापन पर डाटा एकत्र करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) की तकनीकी सहायता से विकसित ऑनलाइन मानीटरी प्रणाली है। आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, सीएसएस के अधीन अनुमोदित और न्याय विकास पोर्टल पर जियो-टैग की गई परियोजना के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर है।

1993-94 में स्कीम के आरंभ से अब तक आंध्र प्रदेश राज्य को 273.23 करोड़ रुपये की रकम जारी की जा चुकी है, जिसमें से पिछले पांच वर्ष के दौरान 151.12 करोड़ रुपये (जिसके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य के हिस्से भी हैं) जारी किए गए हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है -

(रकम करोड़ रुपये में)				
क्र. सं.	वर्ष	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई
1.	2020-21	10.28 (सीएस) + 9.12 (एसएस)	19.40	19.40
2.	2021-22	0.00 (सीएस) + 12.98 (एसएस)	12.98	12.98
3.	2022-23	22.50 (सीएस) + 27.17 (एसएस)	49.67	48.85
4.	2023-24	49.81 (सीएस) + 17.61 (एसएस)	67.42	65.31
5.	2024-25 (तारीख...)*	0.99 (सीएस) + 0.66 (एसएस)	1.65	1.65
<b>कुल</b>		<b>151.12</b>	<b>151.12</b>	<b>151.12</b>

\* एसएनए-स्पर्श सीएस के अधीन जारी:  
सीएस:केंद्रीय हिस्सा, एसएस: राज्य हिस्सा

आज की तारीख में, राज्य में 661 न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं। 81 न्यायालय हॉल और 14 आवासीय इकाइयां संनिर्माणाधीन हैं। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है और भारत सरकार, इस संबंध में राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करती है। परियोजना को समय पर पूरा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों और उनके अधिकरणों की है। स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समयबद्ध और सतत अवसंरचना विकास के लिए मानीटरी तंत्र विद्यमान हैं। स्कीम के अधीन चल रही परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में राज्य में उच्च न्यायालय स्तरीय मानीटरी समिति है। इसके अतिरिक्त, परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए न्याय विभाग में केंद्रीय स्तरीय मानीटरी समिति है। इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा वास्तविक सूचना प्राप्त करने के लिए राज्यों के नियमित दौरे किए जाते हैं। परियोजनाओं की वास्तविक समय मानीटरी के लिए न्याय विकास पोर्टल पर उपलब्ध जियो-टैगिंग सुविधाओं के अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें भी होती हैं। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रशासनिक मंजूरी के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के समक्ष लंबित परियोजनाओं के ब्यौरे **उपाबंध-2** पर है।

\*\*\*\*\*

## 28.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4738 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

न्याय विकास पोर्टल पर उपलब्ध आंध्र प्रदेश जियोटैग परियोजना के ब्यौरे					
क्रम सं.	परियोजना का नाम	जिला	प्रास्थिति	न्यायालय हॉल की सं.	आवासीय इकाइयों की सं.
1	धर्मावरम में नव स्थापित ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय के लिए भवन जी 2 का संनिर्माण	अनंतपुर	सीएमपी	1	1
2	हिंदूपुर में विद्यमान ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन पर अपर जिला न्यायालय भवन का संनिर्माण	अनंतपुर	सीएमपी	1	0
3	हिंदूपुर में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश और कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	अनंतपुर	सीएमपी	0	0
4	चित्तूर जिले के पालमनेर में चार न्यायालय भवन परिसर और आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	चित्तूर	यूसी	4	4
5	चित्तूर जिले के पकाता में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए न्यायालय भवन का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	1	0
6	चित्तूर जिले के थंबल्लापल्ले में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	0	1
7	चित्तूर जिले के मदनपल्ली में विद्यमान द्वितीय अपर न्यायाधीश न्यायालय भवन पर प्रथम तल का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	1	0
8	चित्तूर जिले के पुंगनूर में न्यायिक अधिकारियों के लिए चार आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	चित्तूर	यूसी	0	4
9	चित्तूर में 15 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	चित्तूर	यूसी	15	1
10	पुंगनूर में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	1	0
11	श्रीकालहस्ती में 2 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	2	0
12	मैडुकुर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के लिए 2 न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	कुडुप्पा	सीएमपी	2	0
13	रायचोटी में अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय परिसर भवन का संनिर्माण	कुडुप्पा	सीएमपी	1	0
14	रेलवे कोडुर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	कुडुप्पा	सीएमपी	1	0

15	सिद्धौत में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	कुडुप्पा	यूसी	1	0
16	प्रोड्डातुर पार्ट बी दूसरी मंजिल पर 4 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कुडुप्पा	सीएमपी	1	0
17	ईजी जिले में तुनी में अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए विद्यमान पीजेसीजे क्वार्टर पर प्रथम तल का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	0	1
18	जिला न्यायालय राजामहेंद्रवरम में विद्यमान कुटुंब न्यायालय भवन पर प्रथम तल का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0
19	पूर्वी गोदावरी जिले में राजमहेंद्रवरम में दस न्यायालय भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	यूसी	10	0
20	पूर्वी गोदावरी जिले के रामचंद्रपुरम में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	यूसी	0	1
21	पूर्वी गोदावरी जिले के प्रतिपाडु में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	0	1
22	प्रतिपाडु में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	1	0
23	काकीनाडा में तृतीय अपर जिला न्यायालय भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0
24	अपर ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायालय को समायोजित करने के लिए काकीनाडा में विद्यमान आबकारी न्यायालय के ऊपर 3 तलों का संनिर्माण ।	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0
25	अमलापुरम में विद्यमान 4 न्यायालय भवन परिसर पर तीसरा तल का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0
26	मुम्मिदिवरम में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	1	0
27	अमलापुरम में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	0	0
28	पीतापुरम में नव स्थापित अपर जिला और सत्र न्यायालय को समायोजित करने के लिए भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0
29	नरसरावपेट में 13 अपर जिला न्यायाधीश और प्रधान सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	गंटूर	सीएमपी	0	0

30	ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश मंगलगिरि के लिए विद्यमान क्वार्टर मंगलगिरी पर पहला तल का संनिर्माण	गंदूर	सीएमपी	0	0
31	मछलीपट्टनम में जिला न्यायालय में त्वरित निपटान न्यायालय भवन पर पहला तल का संनिर्माण	कृष्णा	सीएमपी	1	0
32	अवनीगड्डा में दो न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कृष्णा	सीएमपी	2	0
33	कैकलूर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए न्यायालय भवन का संनिर्माण	कृष्णा	सीएमपी	1	0
34	कैकलूर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश को आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	कृष्णा	सीएमपी	0	1
35	गुडीवाड़ा में 11 अपर जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	कृष्णा	यूसी	0	0
36	विजयवाड़ा में पुराने उप न्यायालय भवन को गिराने के पश्चात बहुमंजिला न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कृष्णा	यूसी	26	1
37	नंदीगामा में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश और अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए 2 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कृष्णा	यूसी	2	0
38	कुरनूल जिले के अदोनी में नए छह न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कुरनूल	यूसी	6	0
39	कुरनूल जिले के धोन में चार न्यायालय भवन (स्टिल्ट 3 मंजिल) का संनिर्माण	कुरनूल	यूसी	4	0
40	कुरनूल में 4 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कुरनूल	सीएमपी	4	1
41	नंदयाल में 8 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कुरनूल	सीएमपी	8	0
42	नेल्लोर में प्रधान जिला परिसर में 6 न्यायालय भवनों का संनिर्माण	नेल्लोर	सीएमपी	6	0
43	गुदुर में विद्यमान दो न्यायालय भवन परिसर में पहला तल का संनिर्माण	नेल्लोर	यूसी	2	0
44	नायडूपेट में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय को आवास प्रदान करने के लिए भवन का संनिर्माण	नेल्लोर	सीएमपी	1	2
45	प्रकाशम जिले के गिदलूर में अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	0	1

46	मरकापुर में अपर जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर और संयुक्त दीवार का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	0	1
47	मरकापुर न्यायालय परिसर में उपलब्ध रिक्त स्थल में दो न्यायालय भवन (जी+1) का संनिर्माण	प्रकाशम	यूसी	2	0
48	गिदालुर में दो न्यायालय परिसर का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	2	0
49	मरकापुर में दो न्यायालय परिसर का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	2	8
50	ओंगोल में न्यायिक अधिकारियों के लिए 8 क्वार्टर का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	0	4
51	ओंगोल में न्यायिक अधिकारियों के लिए 4 क्वार्टर ब्लॉक का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	0	1
52	श्रीकाकुलम जिले के कोटाबोम्बाली में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	श्रीकियाकुलम	सीएमपी	1	0
53	श्रीकाकुलम में चार न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	श्रीकियाकुलम	सीएमपी	4	0
54	पालकोंडा में एकल न्यायालय भवन का संनिर्माण	श्रीकियाकुलम	सीएमपी	1	2
55	विशाखापत्तनम जिले के चोडावरम में चार न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	यूसी	4	0
56	नरसीपट्टनम में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	सीएमपी	1	0
57	गजुवाका में दो न्यायालय भवन पर अतिरिक्त न्यायालय का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	सीएमपी	2	0
58	अराकू में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	सीएमपी	0	0
59	विशाखापत्तनम में चार न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	यूसी	4	0
60	सलूर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	विजयानगरम	सीएमपी	2	0
61	विजयानगरम जिले के पार्वतीपुरम में प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश आवासीय क्वार्टरों का संनिर्माण	विजयानगरम	यूसी	0	1
62	विजयानगरम जिले के पार्वतीपुरम में अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश आवासीय क्वार्टरों का संनिर्माण	विजयानगरम	यूसी	0	1

63	विजयानगरम जिले के पार्वतीपुरम में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	विजयानगरम	यूसी	0	1
64	पार्वतीपुरम में सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	विजयानगरम	सीएमपी	0	0
65	पार्वतीपुरम में 2 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	विजयानगरम	सीएमपी	2	0
66	कुरुपम में न्यायालय भवन और आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	विजयानगरम	सीएमपी	1	0
67	पश्चिम गोदावरी जिले के एलुरु में जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	पश्चिम गोदावरी	सीएमपी	0	1
68	पश्चिमी गोदावरी जिले के तनुकू में विद्यमान ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश भवन पर पहला तल का संनिर्माण	पश्चिम गोदावरी	यूसी	2	0
69	पालकोल में प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय के विद्यमान भूमि तल पर पहला तल का संनिर्माण	पश्चिम गोदावरी	सीएमपी	1	0

सीएमपी: पूर्ण, यूसी: संनिर्माणाधीन  
स्रोत: न्याय विकास पोर्टल

**28.03.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 4738 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**  
**प्रशासनिक मंजूरी के लिए सरकार के समक्ष लंबित परियोजनाएं**

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	तारीख जिस पर सरकार को पत्र अग्रेषित किया गया	रु./- में रकम
	अनंतपुर जिला		
1	जिला न्यायालय परिसर, अनंतपुर में छह न्यायालय भवन का संनिर्माण ।	आरओसी.सं. 1349/2013-डीआईआई (बी), तारीख 17.06.2023	19,44,00,000/-
	चित्तूर जिला		
2	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों में अभिगृहीत किए गए विनिषिद्ध/गांजे को न्यायालय परिसर, चित्तूर में अभिज्ञात स्थल के भीतर संरक्षित करने के लिए भंडारण भवन का संनिर्माण ।	आरओसी.सं. 323/2021-डीआईआई (बी), तारीख 28.07.2022	50,00,000/-
3	श्रीकालहस्ती में न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन भवन का संनिर्माण ।	आरओसी.नं. 234/2022-डीआईआई (बी), तारीख 28.10.2024	75,00,000/-
4	चतुर्थ अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के कार्यालय के लिए अस्थायी संरचना का संनिर्माण ।	आरओसी.सं. 162/2021-डीआईआई (बी) तारीख 25.1.2024।	46,00,000/-
5	तिरुपति में विद्यमान न्यायाधीश निलयम में तीन आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण (3,25,00,000/- के सामने पुनरीक्षित)	आरओसी.सं. 1081/2013 तारीख 21.2.2024	3,87,00,000/-
	पूर्वी गोदावरी जिला		
6	प्रतिपाडु में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय भवन का संनिर्माण । (4,19,20,000/- रुपये की रकम के सामने पुनरीक्षित)	आरओसी.सं. 1358/2007-डीआईआई (बी), तारीख 31.12.2018	5,64,00,000/-
7	ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, कोठापेट को आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण (1,50,00,000/- के बजाय पुनरीक्षित प्रशासनिक मंजूरी)	आरओसी.सं. 1542/2012-डीआईआई (बी), तारीख 6.09.2024	1,60,00,000/-
8	राजमहेंद्रवरम में न्यायिक अतिथि गृह का संनिर्माण । (75.00 लाख के बजाय)	आरओसी.सं. 63/2019-डीआईआई (बी), तारीख 13.11.2024	1,00,00,000/-
9	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों में अभिगृहीत किए गए विनिषिद्ध /गांजे को परिरक्षित करने के लिए भंडारण भवन का संनिर्माण । (24.00 लाख के बजाय)	आरओसी.सं. 162/2021-डीआईआई (बी), तारीख 20.09.2024	28,00,000/-
10	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मुम्मिदिवरम को आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण । (रु. 1,45,00,000/- के बजाय)	आरओसी.नं. 272/2022-डीआईआई (बी), तारीख 13.11.2024	1,49,00,000/-
11	(ii) काकीनाडा के विद्यमान आबकारी न्यायालय भवन में 2 मंजिलों में आंतरिक और बाह्य विद्युतीकरण, अभिशमन यंत्र और लिफ्ट व्यवस्था की व्यवस्था करना।	आरओसी.नं. 834/2013-डीआईआई (बी), तारीख 04.11.2023	53,50,000/-
	गुंटूर जिला		
12	तेनाली में बार एसोसिएशन भवन का संनिर्माण । (31.00 लाख के बजाय)	आरओसी.नं. 760/2022-डीआईआई (बी), तारीख 13.11.2024	57,00,000/-
	कडपा जिला		
13	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश , रेलवे कोडुर के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण । (पुनरीक्षित प्रशासनिक मंजूरी)	आरओसी.सं. 558/2008-डीआईआई (बी), तारीख 2.12.2024	1,30,00,000/-
14	कडपा जिले के प्रोद्गातुर में चार न्यायालय भवन परिसर के लिए दूसरी मंजिल, आंतरिक सड़कों,	आरओसी.नं. 438/2005-डीआईआई (बी), तारीख	6,58,00,000/-



	परिसर की दीवार और विद्दुत के कार्य पर अधूरे कार्य को पूरा करना।	18.12.2023	
15	बार एसोसिएशन भवन, कडवा की छत पर सम्मेलन हॉल-सह-विधिक अनुसंधान केंद्रीय का संनिर्माण।	आरओसी.सं. 517/2022-डीआईआई (बी), तारीख 13.12.2023	1,35,00,000/-
16	जिला न्यायालय परिसर, कडवा में दांडिक न्यायालय परिसर (जी + 5) का संनिर्माण (8 न्यायालय हॉल)	आरओसी.नं.1201/2017-डीआईआई (बी), तारीख 28.11.2024	28,90,00,000/-
17	मैडुरुर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय में परिसर की दीवार, सीसी फुटपाथ और सीसी नालियों और पार्किंग शेड का संनिर्माण। (रु. 2,04,00,000/- के बजाय)	आरओसी.नं.976/2014-डीआईआई (बी), तारीख 5.12.2024	1,95,00,000/-
18	नंदालुर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश को एकल न्यायालय भवन और आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण।	आरओसी.नं.327/2015, तारीख 20.11.2024	6,60,00,000/-
	कृष्णा जिला		
19	नंदीगामा के दो न्यायालय भवन के चल रहे संनिर्माण पर प्रथम तल पर 16 अपर जिला न्यायाधीश और प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए दो न्यायालयों का संनिर्माण। (अतिरिक्त रकम)	आरओसी.नं.906/2011-डीआईआई (बी), तारीख 06.02.2023	3,30,00,000/-
20	मायलावरम में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय भवन का संनिर्माण।	आरओसी.नं.162/2021-डीआईआई (बी), तारीख 11.05.2023	4,75,00,000/-
	प्रकाशम जिला		
21	मरकापुर में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण। (110.00 लाख के बजाय)	आरओसी.सं. 661/2018-डीआईआई (बी), तारीख 13.11.2024।	1,50,00,000/-
22	परचूर में विद्यमान ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय भवन का नवीनीकरण।	आरओसी.नं.308/2023-डीआईआई (बी), तारीख 27.12.2023	1,77,00,000/-
23	चिराला में अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	आरओसी.क्र.1154/2013-डीआईआई (बी) तारीख 7.12.2024	1,51,00,000/-
	श्रीकाकुलम जिला		
24	कोथुरु, श्रीकाकुलम जिले में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण।	आरओसी.नं.330/2019-डीआईआई (बी), तारीख 14.09.2022	5,51,00,000/-
25	टेककली में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश के आवासीय क्वार्टर (दुहरे प्रकार का क्वार्टर) का संनिर्माण	Roc.No.665/2021-DII(B), dt.05.12.2022	2,80,00,000/-
26	श्रीकाकुलम जिले के टेककली में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन (दो न्यायालय भवन) का संनिर्माण। (रु. 12,10,00,000/- के बजाय)	आरओसी.नं.302/2022-डीआईआई (बी), तारीख 03.04.2024	11,90,00,000/-
27	पलासा, श्रीकाकुलम जिले में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण। (आरएस)	आरओसी.नं.1001/2017-डीआईआई (बी) तारीख 4.4.2024	5,90,00,000/-
	विशाखापट्टनम		
28	गजुवाका में अपर जिला न्यायाधीश के क्वार्टर (दो क्वार्टर) का संनिर्माण। (आरएस)	आरओसी सं. 751/2014-डीआईआई (बी) तारीख 6.4.2024	3,72,00,000/-
	विजयनगरम जिला		
29	कोठावलसा में एकल न्यायालय भवन का संनिर्माण।	आरओसी.नं.379/2020-डीआईआई (बी), तारीख 18.04.2023	4,68,00,000/-
	पश्चिम गोदावरी जिला		
30	ताडपल्लीगुडेम में न्यायालय परिसर में पुस्तकालय कक्ष का संनिर्माण।	आरओसी.नं.1378/2018-डीआईआई (बी), तारीख	18,00,000/-

		27.02.2018	
31	तनुकु में अपर जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण (1,70,00,000/- के बजाय)	आरओसी.नं.633/2016-डीआईआई (बी), तारीख 24.10.2024	1,77,00,000/-
32	ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, नरसापुर के आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण ।	आरओसी.नं.594/2018-डीआईआई (बी), तारीख 18.09.2021	1,25,00,000/-

\*\*\*\*\*